दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 01 दिसंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 64

महत्वपूर्ण एवं खास

मुरैना में बिजली कर्मचारियों से मारपीट, मामला दर्ज

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बिजली बिल की वसूली करने गए बिजली कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। इस मामले में पीड़ित कर्मचारियों ने तीन लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया गया है कि कंपनी के मुरैना वृत्त के सबलगढ़ संभाग अंतर्गत जौरा वितरण केन्द्र के कर्मचारी लंबित बकाया राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, जाति सूचक गालियां एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा जौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के संबंध में कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।

वन क्षेत्र में लगी भीषण आग

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के उपनगर गोरेगांव के इन्फिनिटी आईटी पार्क के पीछे घने जंगलों में बीती देर रात भीषण आग लग गयी। यह पहाड़ी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा बतायी गयी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कीड़े, पक्षियों और पौधों के जीवन के अलावा तेंदुए, मोर, हिरण और हॉग सहित कई बड़े और छोटे वन्यजीव हैं। आग बुझाने के लिए दमकल की चार गाडिय़ां और पानी के दो टैंकर लगे हुए हैं, आग लगने की घटना रात 11 बजे की है। आग बुझाने के लिए पुलिस विभाग, वन एवं वार्ड के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह लेवल-01 की आग है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है और विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

ईडी ने गुरुग्राम की कंपनी 'बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी धन शोधन जांच के सिलसिले में एक अन्य कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अरोड़ा गुरुग्राम स्थित 'बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। मामले में ईडी द्वारा यह छठी गिरफ्तारी है। सूत्रों के मुताबिक, अरोड़ा को मंगलवार रात धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि अरोड़ा को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां जांच एजेंसी उनकी हिरासत के लिए अनुरोध करेगी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के बाद यह मामला दर्ज किया था।

रियर एडमिरल गुरचरण ने पूर्वी बेड़े की कमान संभाली

विशाखापत्तनम (आरएनएस)। रियर एडमिरल गुरचरण सिंह ने रियर एडमिरल संजय भल्ला से पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) की स्वॉर्ड आर्म, पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। यहां नौसेना की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंगलवार को नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक शानदार समारोह में 'गार्ड ऑफ चेंज 'कार्यक्रम हुआ। रियर एडमिरल गुरचरण सिंह को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और वे गनरी और मिसाइल युद्ध में विशेषज्ञ हैं। फ्लैग ऑफिसर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला ,रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन; नेवल वॉर कॉलेज, गोवा और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। बत्तीस साल के अपने शानदार करियर के दौरान फ्लैग ऑफिसर ने फ्रंटलाइन युद्धपोत रंजीत, प्रहार और ब्रह्मपुत्र पर विभिन्न पदों पर अपनी सेवायें दी है। वह गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक के कमीशनिंग कार्यकारी अधिकारी भी रहे है।

छत्तीसगढ़ में मछलियों के जेनेटिक्स में किया जा रहा अनुसंधान

- थाईलैंड के वैज्ञानिक दे रहे तकनीकी सहयोग
- बलौदाबाजार भाटापारा के रामपुर में लगभग 100 एकड़ में स्थापित किया गया है एक्वा जेनेटिक्स
- निजी क्षेत्र में स्थापित देश का पहला अनुसंधान केन्द्र
- एनएफडीबी की सीई डॉ. सुवर्णा छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यो में शामिल है। अब यहॉ मछली अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की इकाईया भी आगे आ रही है। राजधानी रायपुर से लगे ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केन्द्र स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी (ष्टद्धद्वद्गद्ध श्व&द्गष्ह्लह्लद्व1द्ग) डॉ. सी. सुवर्णा यहॉ दो दिवसीय दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ पहुॅची हैं। डॉ. सी. सुवर्णा ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रामपुर में संचालित मछली पालन उक्त की एक्वा जेनेटिक केन्द्र का अवलोकन किया। साथ ही डॉ. सुवर्णा ने इसी जिले के सिमगा विकासखण्ड के ग्राम बाईकोनी में स्थित प्रतिदिन 100 टन उत्पादन की क्षमता वाले वृहद निजी मत्स्य आहार केन्द्र का शुभारंभ भी किया। यह मंडल एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड स्थापित किया जा रहा है। डॉ. सुवर्णा ने मत्स्य पालन के क्षेत्र मे महिला समूहों और किसानों से मुलाकात की और उनका उत्साह वर्धन किया।

मुख्य कार्यकारी डॉ. सुवर्णा ने छत्तीसगढ़ में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना की और छत्तसीगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंनें मछली पालन के लिए छत्तीसगढ़ को मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉ. सुवर्णा ने कहा की यह बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हर घटक पर तेजी से और वैज्ञानिक तरीके से प्रगति कर रहा है। यहा महिला समूहों द्वारा जो खुले खदानों में मत्स्य पालन का कार्य प्रेरणादायी है।

गौरतलब है कि एक्वा जेनेटिक के इस केन्द्र की स्थापना एम हेचरी रायपुर एवम् मनीत ग्रुप थाईलैंड के संयुक्त उपक्रम द्वारा की गई है। इस अनुसंधान केन्द्र में थाईलैंड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही प्रशिक्षण भी देंगें। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैले इस अनुसंधान केन्द्र में मछली के जेनेटिक्स पर अनुसंधान के साथ-साथ तिलापिया मछली बीज का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहॉ मत्स्य कृषकों को मछली पालन के अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का यह पहला केन्द्र है।

ग्राम रामपुर में स्थापित अनुसंधान केन्द्र से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों को उन्नत किस्म के मछली के बीज की की आपूर्ति हो सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेगा। इसके इलावा वृहद मत्स्य आहार केन्द्र के प्रारंभ होने से प्रदेश के किसानों को स्थानीय स्तर पर कम दर पर मत्स्य आहार प्राप्त हो सकेगा।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की सीई डॉ. सुवर्णा ने सिमगा विकासखण्ड के ग्राम खेरवारी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा बंद हो चुके खदानों में केज कल्चर विधि से किये जा रहे मछली पालन का भी अवलोकन किया। समूह द्वारा यहॉ मछली पालन के लिए 12 केज तैयार किये गए इस प्रोजेक्ट की लागत 36 लाख रूपए है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत और डी.एम.एफ से 40 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। अपने प्रवास के दौरान उन्होंनें रायपुर जिले के तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम पीकरीडीह स्थित वृहद बायोफ्लोक यूनिट का का भी अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना के लिए कृषक श्रीमति अंजू मिश्रा को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि अनुदान मिला है इस इकाई की कुल लागत 50 लाख रूपए हैं। इस इकाई में तीलापाईया और सिंगीं मछली का पालन किया जा रहा है।

कोहरे का कहर : ट्रक-बस की टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 15 घायल; सीएम ने जताया दुख

बहराइच (आरएनएस)। बहराइच जिले के टप्पे सिपाह क्षेत्र में बुधवार को एक बस और ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह साढ़े चार बजे के करीब हुआ, जब कोहरे की वजह से तेज रफ़्तार ट्रक लखनऊ ईदगाह डिपो की रोडवेज को साइड से टक्कर मार दी। हादसा जरवल थाना क्षेत्र के घर्घरा घाट के समीप की है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर सीओ और एसडीएम कैसरगंज मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू करवाया। हादसे का शिकार हुई बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी।

जिलाधिकारी दिनेश चंद्रा ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक गलत साइड से आ रहा था, जब उसने रोडवेज बस को टक्कर मारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई मौत पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

असम-मेघालय सीमा पर गोलीबारी, एनएचआरसी ने निवारण के लिए मांगे सुझाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने असम-मेघालय सीमा पर 22 नवंबर को हुई गोलीबारी की घटना का संज्ञान लिया है और केंद्रीय गृह सचिव और असम के मुख्य सचिव से दो राज्यों के बीच विवाद वाले क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दो सप्ताह के भीतर उपाय सुझाने को कहा है। 22 नवंबर की घटना में मेघालय के पांच ग्रामीणों और असम के एक वन रक्षक की मौत हो गई थी और दो अन्य नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

एनएचआरसी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा द्वारा सौंपे गए एक ज्ञापन का संज्ञान लिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि नवंबर में पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के मुकरोह गांव में असम पुलिस और असम वन रक्षकों द्वारा की गई गोलीबारी में एक असम वन रक्षक सहित छह लोगों की मौत हो गई थी।

मंगलवार को एक बयान में कहा गया है कि आयोग को ऐसा लगता है कि यह घटना दो राज्यों असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के कारण हुई है, जो एक बड़ा मुद्दा है और लंबे समय से लंबित है।

इसमें कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इस विवाद का समाधान हो जाता तो यह घटना टल जाती।

एनएचआरसी ने कहा, राज्यों के बीच जो भी विवाद हो, पुलिस को ऐसी स्थितियों में संयम बरतना होगा।

आयोग ने मेघालय के मुख्यमंत्री का ज्ञापन गृह सचिव और असम के मुख्य सचिव को भेज दिया है।

बयान में कहा गया है, उन्हें तंत्र की जांच और विकास करना है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद है। जवाब दो सप्ताह में मिलने की उम्मीद है।

एनएचआरसी ने कहा कि कथित तौर पर असम पुलिस और असम वन रक्षकों द्वारा लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक का पीछा करने के बाद यह घटना हुई।

इन बलों द्वारा ट्रक को मुकरोह गांव में घेर लिया गया था। ग्रामीण अपने गांव में असम पुलिस के प्रवेश से आक्रोशित हो गए।

बयान में कहा गया है कि उन्होंने असम पुलिस और असम वन रक्षकों को घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी हुई।

घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया।

सड़क एवं पुलों के 520 कार्यों के लिए मिली 5680 करोड़ रूपए की स्वीकृति

- पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर जारी है सडक़ों एवं पुल-पुलियों के निर्माण का कार्य

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में आवागमन के साधनों को मजबूत करने के लिए सडक़ों एवं पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ रोड़ एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में आवागमन के साधनों की मजबूती हेतु कुल 520 कार्यों के लिए 5680 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। इसमें 3110 किमी. की लंबाई वाले महत्त्वपूर्ण 429 मार्गों के लिये 4891 करोड़ रूपए तथा 91 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण कार्यों हेतु 788 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। इसके तहत् अभी तक कुल 492 कार्यों हेतु 5460 करोड़ रूपए की लागत वाले कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ रोड़ एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्यों पर अब तक 1109 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। वर्तमान में समस्त कार्य प्रगति पर है एवं निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिये जायेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में सडक़ों के गड्ढों की भराई एवं सडक़ों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के परियोजना मण्डल बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 1258 कि.मी. लंबाई की कुल 352 सडक़ों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए लगभग 160 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण के लिए कुल 67 सडक़, लंबाई 252.975 किलोमीटर के लिए 78 करोड़ 97 लाख 8028 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कबीरधाम से प्रमुख पर्यटन, धार्मिक एवं जन आस्था का केन्द्र भोरमदेव मंदिर पहुंच मार्ग 16 किलोमीटर सडक़ लगभग 9 करोड़ 60 लाख 24 हजार रूपए की लागत से डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिसे दिसबंर माह तक पूरा कर किया जाएगा। इसी तरह से पूरे प्रदेश में सडक़ों का निर्माण, मरम्मत तथा डामरीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सभी जिलों के कलेक्टर स्वयं इन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर जाकर सडक़ों एवं पुलों की गुणवत्ता भी परख रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके।

मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

बालाघाट (आरएनएस)। आज सुबह सुपखार व मंडला के जंगल में हाकफोर्स की सर्चिंग टीम व नक्सली आमने-सामने हो गए। इस दौरान दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान उठाना पड़ा है। जिसमें दो ईनामी नक्सलियों की मौत होने की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने की है। वहीं पुलिस एक नक्सली को गोली लगने से वह घायल हो गया है। जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कान्हा भोरम दलम के वर्दीधारी नक्सलियों की सुपखार व मंडला के जंगल में होने की सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद हाकफोर्स की सर्चिंग पार्टी को जंगल में रवाना किया गया। यहां पर सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने सर्चिंग पार्टी को देख उनके उपर फायरिंग शुरु कर दी। जिसके बाद हॉकफोर्स ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें दो नक्सलियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य नक्सली को भी गोली लगने से वह घायल हो गया है।

नक्सली मुठभेड़ के बाद घटना स्थल पर बालाघाट, मंडला व छत्तीसगढ़ के एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए है और घटना स्थल के जंगल के साथ ही आसपास के जंगल की सर्चिंग कर रहे घायल हुए नक्सली की तलाश में लगे हुए है। हालांकि इन बड़े अधिकारियों के जंगल में होने के कारण मारे गए नक्सलियों के नामों की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं मारे गए एक नक्सली का नाम गणेश बताया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

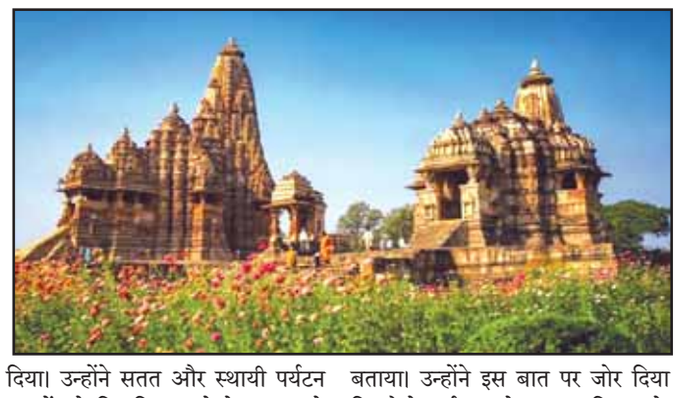

नईदिल्ली (आरएनएस)। सतत और स्थायी पर्यटन स्थलों को विकसित करने और देश में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आईआईटीटीएम, यूएनईपी और आरटीएसओआई के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने 29 नवंबर को खजुराहो में भरोसेमंद और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एवं दीव और गोवा के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और पर्यटन उद्योग के हितधारकों की व्यापक भागीदारी हुई।

पर्यटन मंत्रालय में निदेशक प्रशांत रंजन ने इस कार्यशाला में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने सतत और स्थायी पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यटन में निरंतरता और केन्द्र, राज्य एवं उद्योग जगत के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता के संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे पर्यटन को लाइफ मिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने इस कार्यशाला में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान को पेश किया।

पर्यटन मंत्रालय में सहायक महानिदेशक उत्तंक जोशी ने देश में पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को तैयार करने से संबंधित पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजना 'स्वदेश दर्शन 1.0' की सफलता की कहानियों को साझा किया। उन्होंने स्वदेश दर्शन 2.0 की रूपरेखा पेश की और यह भी बताया कि यह योजना कैसे पर्यटन से जुड़े गंतव्यों के विकास में स्थिरता को एकीकृत करती है।

अनिरुद्ध चाओजी, जोकि एक प्रतिष्ठित इको-टूरिज्म व्यवसायी और आरटीएसओआई के प्रतिनिधि हैं, ने प्रतिभागियों के साथ पर्यटकों को संवेदनशील बनाने और जिम्मेदार यात्रा की मांग सृजित करने के बारे में विचार-विमर्श किया।

सुमनीषा चौधरी ने जलवायु परिवर्तन कॉप 26 में नवंबर 2021 में शुरू की गई वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल और पर्यटन में जलवायु कार्रवाई पर ग्लासगो घोषणा जैसे कुछ ऐतिहासिक प्रयासों को साझा किया। उन्होंने हितधारकों को इस तरह की पहल में शामिल होने और सतत विकास के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता की हानि जैसे इस धरती के तिहरे संकट को दूर करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों के प्रतिनिधियों ने भी टिकाऊ पर्यटन से संबंधित उनकी उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुतियां दी।

टिकाऊ पर्यटन से संबंधित केन्द्रीय नोडल एजेंसी, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ने प्रतिभागियों को भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। प्रतिभागियों ने जिम्मेदारी से यात्रा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ प्रतिज्ञा भी ली।

जमीनी स्तर के उद्योग के हितधारकों ने मूर्त सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में टिकाऊ पर्यटन को लागू करने के अपने नवीन तरीके भी प्रस्तुत किए।

इस कार्यशाला ने पर्यटन में स्थायित्व संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और उद्योग जगत के हितधारकों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया।